के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने हैं और अप्रैल में अकातोज के अवसर पर ये कार्यक्रम चरण सीमा पर होंगे।

5. बालिकाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार को स्वीकारते हुए राष्ट्रीय विकास योजना में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बालिकाओं की स्थिति पर नजर रखी जा सके।

6. 18 वर्ष की आयु तक लड़कियों की शादी टालने के लिए लड़कियों और उनके परिवार को प्रोत्साहन देने हेतु प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये 4 राज्यों में किशोरी विकास केन्द्रों की स्थापना करना।

7. निर्धन शहरी बालिकाओं की समस्या के समाधान के लिए नवीन योजनायें समस्या विशेष हों और प्रायोगिक परियोजनाएं हों ताकि उनमें फेरबदल हो सके।

अखिल भारतीय आंगन बाडी कर्मचारी संघ की मांगें

*1064. **सरदार जगजीत सिंह अरोडा** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने हाल ही में अपनी मांगों के समर्थन में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मांगें क्या हैं,

(ग) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है और उनकी मांगों के संबंध में उनसे बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो यह बातचीत कब हुई थी तथा उसका क्या परिणाम रहा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय कामगार संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारियों के बराबर का दर्जा दिए जाने और सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य नियमित वेतनमान और अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर सरकार को एक ज्ञापन दिया है।

(ग) और (घ) इन दोनों महासंघों के प्रतिनिधि इस विभाग के अधिकारियों से मिले थे। उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई०सी०डी०एस०) की धारणा ग्रामीण स्तर पर स्वयंसेवी सेवाओं तथा सामुदायिक सहभागिता सिद्धान्तों पर आधारित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अंशकालिक, अवैतनिक और स्वयंसेवी कार्यकर्ता होती हैं। उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान नियमित वेतनमान और भत्ते दिया जाना सामुदायिक-सहभागिता की धारणा के विपरीत है। उनसे प्रतिदिन लगभग साढ़े चार घंटे कार्य करने की ही अपेक्षा की जाती है। मांग की भारी वित्तीय कठिनाइयों और इसके व्यापक प्रभावों के अलावा, इन्हीं कारणों से इन कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देना सरकार के लिए संभव नहीं होगा।

Use of cassettes as better baby sitters

**1065. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to a report which appeared in the Economic Times dated the 26th April, 1989 under the caption "Times for Tiny Tots";

(b) if so, whether there is any proposal under Government's consideration to encourage the use of cassettes as better baby sitters; and

(c) if so, what are the details in this regard?

*पूर्वत अतारांकित प्रश्न 771, 15 मई, 1990 से स्थानान्तरित।

**Previously Unstarred Question 802, transferred from the 15th May, 1990.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF WELFARE (SMT. USHA SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

CAG reports on NDDB/IDC

1066. SHRI SHAMIM HASMI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether CAG has highlighted mammoth losses of public sector and if so, whether NDDB/IDC has been covered under this report as appeared in the Times of India, dated the 28th March, 1990;

(b) whether it is a fact that NDDB/IDC had failed to submit vouchers etc. to CAG since 1983-84 as per CAG reports and if so, the corrective action taken or proposed to be taken in this regard; and

(c) whether it is also a fact that the NDDB is the only organisation using Consolidated funds of India since 1987 which is not under the control of CAG as required under the Constitution and if so, the corrective steps proposed to be taken to set this anomaly right?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) The National Dairy Development Board (NDDB)/erstwhile Indian Daity Corporation (IDC) have not been covered under this news item.

(b) The IDC had fully replied to the comments of CAG in their respective years' accounts. The accounts were included in the Annual Report of the erstwhile IDC. In view of this no further action is necessary.

(c) Information is being collected and the same will be placed on the table of the Sabha.

Capacity utilisation of Milk Power Plant and Tetrapack Plant

1067. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1287 given in the Rajya Sabha on the 23rd March, 1990 and state:

(a) the installed capacity and utilisation of milk powder plants in each of the States in the country during December, 1989, January and February, 1990;

(b) the installed capacity of tetrapack units and utilisation, State-wise, during the above period; December 1989, January and February 1990;

(c) whether it is a fact that milk production has increased during the last 3-4 years State-wise despite the drought leading to seasonal surpluses during these years;

(d) whether Government have received a letter dated 21st July, 1986 from Shri Shiaji Rao Moghe requesting NDDB Chairman to lift surplus milk powder of 8000 MT which was turned down by NDDB chairman vide his reply dated 30th July, 1986; and

(e) if so, whether Government would inquire into the matter and punish those responsible therefor; and also inquire into the Basak Committee Report of the 31st December, 1986 and all representation from Maharashtra State Assembly on this subject?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) The installed capacity and utilisation of Milk Powder Plants in each of the States in the country during December, 1989, January and February, 1990 is given in the enclosed statement. (*See* Appendix CLIV Annexure No. 49).